



सत्यमेव जयते

केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)



O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, 7th Floor, Central Excise Building,
सातवीं मंजिल, पॉलिटेकनिक के पास, Near Polytechnic,
आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015 Ambavadi, Ahmedabad-380015

☎ : 079-26305065

टेलीफैक्स : 079 - 26305136

रजिस्टर डाक ए .डी .द्वारा

1000/0
1004

क फाइल संख्या (File No.): V2(76)153/Ahd-II/Appeals-II/ 2016-17

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.): AHM-EXCUS-002-APP- 312-17-18

दिनांक (Date): 30.01.2018 जारी करने की तारीख (Date of issue):

15/2/2018

श्री उमा शंकर, आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by Shri Uma Shanker , Commissioner (Appeals)

ग _____ आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (मंडल-IV), अहमदाबाद- II, आयुक्तालय द्वारा जारी

मूल आदेश सं----- दिनांक -----से सृजित

Arising out of Order-In-Original No . 82/DC/D/2016/RK Dated: 20.12.2016 issued
by: Deputy Commissioner Central Excise (Div-IV), Ahmedabad-II

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवम पता (Name & Address of the Appellant/Respondent)

M/s Royal Touch Aluminium Pvt. Ltd

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

Any person an aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India:

(1) (क) (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धरा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परंतुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को की जानी चाहिए ।

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:

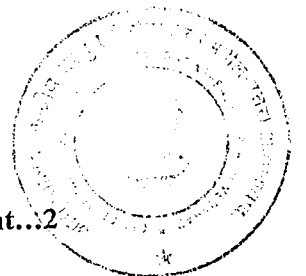
(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब हानि कारखाने से किसी भंडारगार या अन्य कारखाने में या किसी भंडारगार से दूसरे भंडारगार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भंडारगार या भंडार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भंडारगार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो ।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है ।

As file

Cont...2



- (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनोंक से तीन मारु के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- (2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

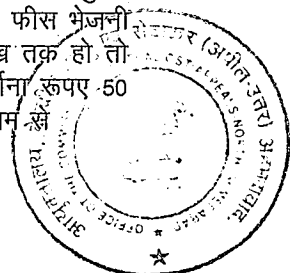
- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिकां वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं

- (a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

- (ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हॉस्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद-380016.

- (b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

- (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से



रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो जहाँ उक्त न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग" (Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

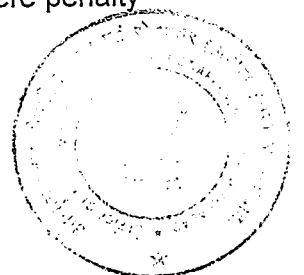
For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस सन्दर्भ में इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

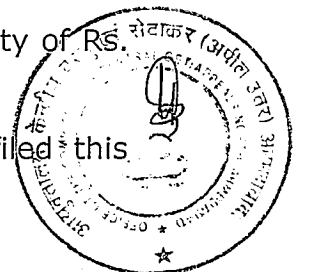


ORDER IN APPEAL

This order arises out of an appeal filed by M/s Royal Touch Aluminium Pvt. Ltd., 17/1 & 18/2 & 18 to 22 & 30 To 32, Saket Industrial Estate, Sarkhej-Bavla Road, Near Nova Petrochemicals, Moraiya, Changodar, Ahmedabad (hereinafter referred to as the "the appellant") against the Order-In-Original No. 82/DC/D/2016/RK dated 20.12.2016 (hereinafter referred to as "the impugned order") passed by the Dy. Commissioner, Division-IV, Ahmedabad-II (hereinafter referred to as "the Adjudicating Authority").

2. The facts in brief are that during the audit verification of the records maintained by the appellant, it was observed that the appellant had received income as "job-work charges" amounting to Rs. 36,81,959/- during the financial year 2012-13 to 2015-16. It was observed that the appellant was doing job-work for M/s Hi-Fab Aluminium who sent raw material i.e. aluminium scrap to the appellant for melting to convert into articles of aluminium i.e. aluminium channels etc. This process amounts to manufacture. Since the job work process amounting to manufacture and intermediate production process which does not amount to manufacture, both should be treated as exempted services as per Rule 2 (e) (1) & (2) of Cenvat Credit Rules, 2004 (herein after referred to as the CCR). Since the job-work carried out by the appellant is exempted from payment of service tax, they were required to maintain separate records of inputs used in dutiable goods as well as exempted services in terms of Rule 6 of the CCR failing which they were required to pay an amount of 5% or 6% on the value of the exempted service in terms of Rule 6 (3) (i) of the CCR. Further, cenvat credit shall not be allowed on such quantity of input used for provision of exempted service except the circumstances mentioned in sub-rule 2. It therefore appeared that the appellant had not followed the procedure spelt out in Rule 6 of the CCR. Accordingly they were issued a show cause notice proposing why the job-work carried out by them should not be treated as exempted service in terms of rule 2 (e) of the CCR; an amount of Rs. 2,20,917/- being an amount payable on value of exempted service should not be recovered from them with interest and why penalty should not be imposed upon them. The adjudicating authority, after having considered all the case records, defence arguments and evidences, confirmed the demand of Rs. 2,20,917/- to be recovered with interest and also imposed penalty of Rs. 1,10,459/- vide the impugned order.

Being aggrieved by the impugned order, the appellant has filed this appeal on the following grounds:



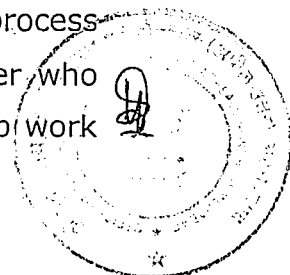
- a) The order has been passed in gross violation of principle of natural justice as the appellant was neither served upon any show cause notice nor was heard before passing the order;
- b) The appellant was not required to pay any service tax and central excise duty as the principal manufacturer used to clear the final goods only on payment of appropriate duty of central excise. The appellant also submitted copies of relevant ER-1 returns filed by the principal manufacturer during the relevant period;
- c) The most of the demand is beyond the normal period of limitation from the date of show cause notice;
- d) The situation was a revenue neutral situation as if the service tax was paid by the appellant, the principal manufacturer would have got cenvat credit so there was no need to evade payment of service tax;

4. The personal hearing held on 09.01.2018 was attended by Shri Devashish K Trivedi, Advocate on behalf of the appellant, who requested for condonation of delay in filing the appeal and reiterated the contents of their appeal memorandum. Further, he submitted the Notification No. 12/2012-ST and 25/2012-ST and sought support from the citation of Federal Mogul Goetze India Ltd. - 2015 (318) ELT-340 (Tri.).

5. At the outset, I observe that the appellant has filed the instant appeal under Section 35 of Central Excise Act, 1944 on 27.03.2017 against the impugned order received by them on 17.01.2017 i.e with a delay of seven days. In view of the provisions, the present appeal is required to be filed within two months from the date of the decision of the adjudicating authority and the Commissioner (Appeals) is empowered to condone the delay in filing of appeal for further period of one month. In the instant case, the appellant has filed the appeal with a delay of seven days and have also given reasons for not being able to file the appeal in time. I condone the delay in filing the appeal as it is well within my competency and I proceed to decide the appeal of the appellant.

5. I find that during the personal hearing the appellants have not pressed their contention made in their grounds of appeal that they were neither served upon any show cause notice nor was heard before passing the order. In view of this, I take up this case for decision by considering rest of their arguments and case records.

6. From the findings of the impugned order, it is very clear that the appellants were engaged in job work i.e they carried out process amounting to manufacture on behalf of the principal manufacturer who sent his goods to the appellants and the appellants carried out job work



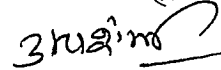
and sent the goods back to the principal manufacture and availed job work exemption provided by the Notification No. 214/86 dtd. 25.03.2086. it is also a fact that Section 65D of the Finance Act, 2012 w.e.f. 01.07.2012 has provided negative list of services which were exempt from payment of service tax and as per clause (f) of Section 6D of the Finance Act, 1994, process which amount to manufacture or production of goods were specified under negative list of service. From these provisions, it is very clear that the process carried out by the appellants was a job work and it amounted to manufacture of final products at the end of the principal manufacturer. Therefore I find that the findings of the impugned order in this regard have to be rejected and I do so.

7. now I take up the issue of rule 6 of the Cenvat Credit Rules, 2004 ('the Rules' for brevity). I have perused the findings recorded by the adjudicating authority and I find that the appellants were a job worker and they were not required to pay any central excise duty as per the impugned order. Accordingly they were not entitled for cenvat credit also and from impugned order, it is not coming out that the appellants availed cenvat credit. No evidence to this effect has been recorded so no question arises for observance of procedure stipulated in Rule 6 of the Rules. In this regard I agree with the contention of the appellants that it was the principal manufacturer who was required to observe and follow the provisions of rule 6 of the Rules. The adjudicating authority has not been able to make out any case of contraventions of the rule 6.

8. In view of facts and discussion herein above, the impugned order is set aside and the appeal is allowed.

9. The appeal filed by the appellant stand disposed off in above terms.

अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।



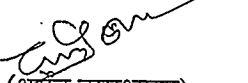
(उमा शंकर)

केंद्रीय कर आयुक्त (अपील्स)

अहमदाबाद

दिनांक:

सत्यापित



(धर्मद्व उपाध्याय)

अधीक्षक (अपील्स),

केंद्रीय कर, अहमदाबाद

By R.P.A.D.

To:

M/s Royal Touch Aluminium Pvt. Ltd.,
17/1 & 18/2 & 18 to 22 & 30 To 32,
Saket Industrial Estate,
Sarkhej-Bavla Road,



Near Nova Petrochemicals,
Moraiya, Changodar,
Ahmedabad

Copy to:-

- (1) The Chief Commissioner, CGST, Ahmedabad Zone,
- (2) The Commissioner, CGST, Ahmedabad (North),
- (3) The Dy./Asth. Comm'r, CGST, Div.-IV, Ahmedabad (North),
- (4) The Dy./Asth. Comm'r (Systems), CGST, Ahmedabad (North),
- (5) Guard File,
- (6) P.A.File.

